IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भूटान के साथ भारत का संबंध : एक व्याख्या

शोधार्थी, आँचल कुमारी विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर – 812007

सारांश

प्रधानमंत्री मोदी भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों की शुरुआत अपने पहले कार्यकाल के दौरान किया अर्थात नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रथम बार प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए तभी उन्होंने पड़ोसी प्रथम नीति का आह्वान अपने शपथ ग्रहण समारोह में पूरे दक्षिण एशिया देशों के राष्ट्रयाध्यक्ष को निमंत्रण देकर इसका प्रारंभ किया था। नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश गंतव्य के रूप में भी भूटान को ही चुना। भूटान के साथ भारत का संबंध अद्वितीय रहा है और इसे आगे बढ़ाने में मोदी जी ने भरपूर प्रयास किया है।

शब्द कूंजी

भारत, भूटान, पड़ोसी प्रथम नीति, दक्षिण एशियाई देश, राष्ट्राध्यक्ष, पड़ोसी देश, सुरक्षा, यात्राएं, घनिष्ठ संबंध।

परिचय

भारत और भूटान के बीच विलक्षण सौहार्दपूर्ण व विशेष संबंध है जो पारस्परिक विश्वास और समझ बूझ पर आधारित है। यात्राओं का नियमित आदान-प्रदान घनिष्ठ परामर्श और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग भूटान के साथ हमारे संबंधों के आधारशिला है। वर्ष 2014 के पूर्व ही प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने यह संकेत दिए थे कि उनकी विदेश नीति भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करेगी,जिसे विशेषज्ञयों द्वारा 'पड़ोसी प्रथम नीति' कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई देशों के सभी राष्ट्रीयाध्यक्ष के प्रमुखों को आमंत्रित करके इसकी शुरुआत की और कार्यकाल के दूसरे दिन उन्होंने उन सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय वार्ता की जिसे मीडिया द्वारा मिनी सार्क शिखर सम्मेलन करार दिया गया। मोदी जी के विदेश नीति दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं।

अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देना भारत की विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत रहा है। उपमहाद्वीप में अपने निकटतम क्षेत्र का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना भारत के लिए एशिया और वैश्वीक स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण है। पड़ोसी देशों में अक्सर होने वाले राजनीतिक या आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत का ध्यान अवसर उपमहाद्वीप की ओर चला जाता है जिसे व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को बोधित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है।

पड़ोसी देशों के बीच वैश्वीक और आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में हाल ही में हुए बदलावों के साथ, भारत के पास अपने पड़ोस प्रथम नीति (NFP) को फिर से जीवंत करने का एक नए अवसर है जिसका उसे पूरे दिन से लाभ उठाना चाहिए। यदि भारत का लक्ष्य क्षेत्र में चीन की गतिशीलता का मुकाबला करना है, तो भूटान के साथ उसके संबंधों में देखी गई गमजोशी और निकटता को पूरे घनिष्ठता और विस्तारित पड़ोस तक बढ़ाया जाना चाहिए।

1947 से पड़ोसी प्रथम की नीति भारत की विश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जो अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और साझा मुद्दों के समाधान पर केंद्रित रही है। पड़ोसी पहले नीति की अवधारणा 2008 में अस्तित्व में आई। अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी

संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत एक सक्रिय विकास भागीदार और इन देशों के कई परियोजनाओं में शामिल है।

भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने का तरीका, परामर्श गैर-पारस्परिकता और ठोस परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, विकास सहयोग और सुरक्षा और लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है।

पड़ोसी प्रथम नीति का उद्देश्य

कनेक्टिविटी

भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। ये समझौता सीमाओं के पार संसाधनों, ऊर्जा, माल, श्रम और सूचना के मुक्त प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं।

पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार

हमारी प्राथमिकता निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करना है, क्योंकि विकास एजेंडा को साकार करने के लिए दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता आवश्यक है। यह पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करके और संवाद के माध्यम से राजनीतिक संपर्क बनाकर सशक्त क्षेत्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करता है।

आर्थिक सहयोग

यह पड़ोसियों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत ने क्षेत्र में विकास के लिए सार्क में भाग लिया और निवेश किया है। इसका एक उदाहरण ऊर्जा विकास अर्थात मोटर वाहन, जल- विद्युत प्रबंधन अंतर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश- भूटान - भारत - नेपाल (बीबीआईएन) समूह है।

भारत के लिए पड़ोसी प्रथम नीति का महत्व

चीनी प्रभाव का प्रतिकार

पड़ोसी देशों के साथ सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र (आईओ आर) में चीनी प्रभाव के मुकाबला करने में भारत के रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है। यह सहयोग क्षेत्र में 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' बनने की भारत की आकांक्षा के अनुरूप है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी।

बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के रूप में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए पड़ोसी साझेदारों के साथ सहयोग आवश्यक है। बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता के माध्यम से भारत द्विपक्षीय संबंधों में क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय आयाम जोड़ता है, जिससे क्षेत्र की गहन समाज विकसित होती है।

क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना

भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और अलगाववादी खतरों से निपटने के प्रयासों के लिए पड़ोसी देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से निपटने में म्यांमार के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान को उजागर करता है।

समुद्री सुरक्षा बढ़ाना

समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी सहयोग आवश्यक है। समुद्री क्षेत्र में खतरे के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, इस तरह का सहयोग भारत को अपने जल क्षेत्र की प्रभावी निगरानी करने तथा आतंकवाद जैसी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है।

ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान

भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेपाल और भूटान जैसे उत्तरी पड़ोसियों तथा हिंद महासागर के देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत के तेल और गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर जाता है, इसलिए ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग अपरिहार्य है।

विकास घाटे को पाटन

पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय भागीदारी से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में भी मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर में माल के परागमन और परिवहन के लिए बांग्लादेश द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग को मंजूरी देना विकास संबंधी अंतराल को पाटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावना को उजागर करता है।

सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का लाभ उठाना

भारत के अपने पड़ोसियों के साथ समृद्ध संस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध इसकी सॉफ्ट पावर कूटनीति की आधारशिला है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और साझा विरासत पर जोर देकर, भारत लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता है, जो राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सॉफ्ट पावर कूटनीति की क्षमता का उदाहरण है।

भारत के पड़ोसी प्रथम नीति में चुनौतियां

तत्काल बनाम विस्तारित पड़ोस

विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत का अपने पड़ोसियों के प्रति दृष्टिकोण मौजूदा रिश्ते का आकार देने से ज्यादा उन्हें प्रतिबंधित करने पर केंद्रित रहा है। स्पष्ट नीतिगत ढांचे की कमी ने क्षेत्रीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। भारत के निकटवर्ती और दूरस्थ पड़ोसियों पर दोहरे फोक्स के कारण दक्षिण एशियाई पड़ोसियों पर स्पष्ट और एकल जोर देने में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए और परिणाम अनिश्चित रहे हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां

क्षेत्र में कुछ देशों के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की है उदाहरण के लिए पिछले सार्क शिखर सम्मेलन में तीन प्रस्तावित समझौता में से केवल एक पर ही हस्ताक्षर किए गए थे क्योंकि पाकिस्तान ने अन्य दो पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

सुरक्षा चिंताएं

पारगम्य सीमाओं का अस्तित्व पाकिस्तान जैसी पड़ोसी देशों के समर्थन और इस क्षेत्र में उग्रवाद का उदय भारत के भीतर आतंकवादी गतिविधियों के उभारने में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रीसेंट से भारत की निकटता इसकी मादक पदार्थों की तस्करी की समस्याओं को बढ़ाती है।

चीन की ओबीओआर पहल का प्रभाव

चीन के वन बेल्ट वन रोड (ओबीआरओ) पहल की कारण सार्क देश के साथ उसके व्यापार में तेजी में वृद्धि हुई है। श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों में कई बार भारत के खिलाफ चीनी कार्ड का इस्तेमाल किया और वैकल्पिक साझेदार की तलाश की है।

असमान व्यवहार की धारणाएं

भारत के पड़ोसी देशों को अक्सर ऐसा लगता है कि भारत उसके साथ समान व्यवहार नहीं करता। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों को भारत के सैन्य भागीदारी को अभी भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबूत के तौर पर देखा जाता है।

खराब बुनियादी ढांचे का प्रभाव

सीमावर्ती क्षेत्र में खराब बुनियादी ढांचा के कारण मुक्त व्यापार निवेश सौदे का प्रभाव सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच आज बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा रेलवे कनेक्शन थे।

घरेलू राजनीतिक विचार

भारत की पड़ोसी नीति अक्सर घरेलू राजनीति कारको और जातीय विचारों से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौते में पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण देरी हुई, और श्रीलंकाई तमिल संघर्ष के कारण समर्थन जातीय संबंधों से प्रेरित था।

भारत की ऋण सहायता के कार्यान्वयन की चुनौतियां

भारत की अपने पड़ोसियों को दी जाने वाले ऋण- सीमा (एलओसी) परियोजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन उनके क्रियान्वयन में देरी हो रही है। इससे निराशा, अविश्वास और क्षेत्र में भारत के प्रभाव की कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता विकास प्रयासों के लिए और अधिक चुनौतियां उत्पन्न करती है।

भारत के पड़ोसी प्रथम नीति को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव

विदेश मामलों की स्थाई समिति ने जुलाई 2023 में भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख टिप्पणी और सिफारिश की इस प्रकार है –

आतंकवाद और अवैध प्रवासन

पिछले 30 वर्षों में भारत को अपने पड़ोसी देशों से खतरों, तनावों और संभावित आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। अवैध प्रवास, हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों को तस्करी जैसी चुनौतियों ने सीमा सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है। समिति ने अवैध प्रवास के परिणामस्वरूप होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों की निगरानी करने का सुझाव दिया है तथा इस मुद्दे से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ सहयोग की वकालत की है।

चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध

चीन और पाकिस्तान के साथ भारत द्विपक्षीय संबंध विवादास्पद मुद्दों से ग्रस्त है, पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद एक प्रमुख चिंता के विषय है। समिति ने आतंकवाद को बढ़ावा देने और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के साथ बातचीत करने की सिफारिश की। पड़ोसी पहले नीति के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि सरकार को पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने चाहिए।

सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में निवेश

समिति ने भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की कमी और सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर और विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। भारत के पड़ोसियों के साथ जुड़ाव के लिए सीमा पर सड़के रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाह जैसे कनेक्टिविटी बुनियादी ढाचों में सुधार की आवश्यकता है। इसने क्षेत्र ढांचा के अंतर्गत कनेक्टिविटी अवसंरचना के लिए क्षेत्रीय विकास निधि की स्थापना की व्यवहार्यता का पता लगाने के सिफारिश की है।

भारत की ऋण सहायता (एलओसी) परियोजनाओं की निगरानी

भारत को अपने पड़ोसियों को दिया गया ऋण 2014 में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 14.7 बिलयन अमेरिकी डॉलर हो गया। समिति ने पाया कि भारत के वैश्विक साफ्ट लैंडिंग का 50% उसके पड़ोसियों को जाता है। इसे विदेश मंत्रालय को नियमित निगरानी के माध्यम से ऐसी LOC परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावित कदम उठाने सिफारिश की। संयुक्त परियोजना निगरानी समितियों और निरक्षण तंत्र को मजबूत करके पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा

रक्षा सहयोग भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव, म्यांमार और नेपाल जैसे विभिन्न देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को भारत के विस्तारित पड़ोस में समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पहल करनी चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास

एक्ट ईस्ट नीति एशिया - प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कई पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए अभिन्न अंग है। समिति ने मंत्रालय को इन दोनों नीतियों के बीच तालमेल बनाए रखने के सिफारिश की। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

पर्यटन संवर्धन

2020 से भारत दक्षिण एशियाई देशों जैसे भूटान के लिए पयटकों के आगमन का सबसे बड़ा स्रोत भूटान रहा है। बांग्लादेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक ईलाज के लिए भारत आते हैं कई भारतीय धार्मिक पर्यटक नेपाल व भूटान जाते हैं। समिति ने पड़ोसी पहले नीति के तहत चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने की सिफारिश की।

बहुपक्षीय संगठन

भारत अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ाव बहुपक्षीय और क्षेत्रीय तंत्रों द्वारा संचालित होता है इसमें सार्क और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शामिल है। समिति ने कहा कि पड़ोस प्रथम नीति का प्रभाव जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से महसूस किया जाना चाहिए इसके लिए संस्थागत और बहूपक्षीय/ क्षेत्रीय तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। समिति ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के ढांचों की समय-समय पर समीक्षा करने की सिफारिश की।

भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत - भूटान संबंध में लाभ

आपसी सम्मान और समन्वय

दोनों राष्ट्र एक - दूसरे को समान मानते हैं, एक दूसरे के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते और लंबे समय से यह महसूस करते आ रहे हैं कि आकर (क्षेत्रफल, जनसंख्या के संदर्भ में) वास्तव में दो संप्रभु राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों में कोई अंतर नहीं डालता हैं।

इस प्रकार भारत ने भूटानी पहचान भूटान की विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं तथा उसकी अपनी जीवन शैली को बरकरार रखते हुए आर्थिक रूप से समृद्ध होने की इच्छा का निरंतर सम्मान किया है। भूटान को लंबे समय से पता है कि उसके दक्षिणी हिस्सों से उसकी संप्रभुता या पहचान को कोई वास्तविक खतरा नहीं है वह अपने विकास और समृद्धि के लिए भारत की ओर देखता रहा है।

सतत परियोजना में सहयोग : गेलेफू

गेलेफू को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के तरह बनाया जाना है, ताकि विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके और उस देश की समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। स्वाभाविक रूप से भारत और उसके व्यापारिक संस्थाओं के इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसके साथ ही गेलेफू माइंडफूलनेस सिटी का उद्देश्य स्थिरता, कल्याण और पर्यावरण संबंधी चिताओं को सर्वोपरि रखना है। ऐसी परियोजनाओं से भूटान के लोगों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है साथ ही कार्बन नकारात्मक देश के रूप में भूटान पर इसके प्रभाव के बारे में किसी भी चिंता को दूर किया जा सके।

निरंतर एवं नियमित संवाद

यह आम समझ है कि किसी भी रिश्ते को चाहे वह दो व्यक्तियों के बीच हो या दो देशों के बीच निरंतर देखभाल नियमित संवाद और बहुत अधिक देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। भूटान और भारत के प्रधानमंत्री की एक दूसरे से लगातार यात्राएं दोनों सरकारों द्वारा संबंधों पर दिए जा रहे ध्यान का प्रकटीकारण है। यह भारत भूटान संबंधों में निरंतर विकास और वृद्धि के लिए एक शुभ संकेत है यह भारत के पड़ोसी प्रथम नीति दृष्टिकोण का प्रतीक है।

जलविद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा सहयोग

जल विद्युत सहयोग भूटान के साथ भारत के संबंध का आधार है। कई सहकारी जल विद्युत परियोजना पूरी हो चुकी है जैसे 1020 मेगावाट की ताला जलविद्युत परियोजना और दोनों सरकार द्वारा शुरु की गई अन्य परियोजना, जो भारत को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति करती है और थिम्पू को राजस्व का एक स्रोत प्रदान करती है जिसके कारण यह सबसे कम विकसित देश के दर्जे से बाहर आ गया है। विलंबित पुनात्सांगछू-2 जल विद्युत परियोजना के 2024 में पूरा होने की उम्मीद है जो जलविद्युत में सहयोग के सरकार से सरकार मॉडल का एक और सफल उदाहरण है।

भारत की विकास सहायता

भारत भूटान का प्रमुख विकास सहायता साझेदारी भी रहा है और उसने हाल ही में समाप्त हुई बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। विकास सहायता के इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत केवल अपने लिए लाभकारी परियोजना ही नहीं चलाता बल्कि भूटानी लोगों की प्राथमिकताओं पर भी काफी ध्यान देता है ताकि उसके लिए सीधे लाभ की परियोजना बनाई जा सके।

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी अब तक तीन बार भूटान का दौरा कर चुके हैं। प्रथम बार उन्होंने 2014 में, दूसरी बार 2019 में और तीसरी 2024 में भूटान गए। हिमालयी राष्ट्र के साथ भारत का संबंध अटूट रहा है इसी अटूट संबंध को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीयाध्यक्ष द्वारा नियमित यात्राएं होती रही है। भारत के 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी का भूटान दौरा यह दर्शाता है कि भारत भूटान को कितना महत्व देता है। मोदी जी का यह दौरा दो दिवसीय था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संचार, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्र में अनेक समझौते हुए और साथ ही दोनों देशों के बीच रेल संपर्क की स्थापना पर सहमति पत्र को अंतिम रूप दिया गया। मोदी जी ने कहा भारत और भूटान के आकांक्षाएं एक जैसे हैं हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का फैसला किया है और भूटान ने भी 2034 तक उच्च आय वाला देश बनने का फैसला किया है। आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत ब्रांड भूटान और भूटान विश्वास के साथ आपके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा भारत भूटान साझेदारी केवल जमीन और पानी तक सीमित नहीं है भूटान अब भारत के अंतरिक्ष मिशन में भी भागीदार है। भूटान के वैज्ञानिकों ने इसरो के साथ मिलकर उपग्रह लांच किए हैं हम एक दूसरे की उपलब्धियां का जश्न मनाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो' पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिससे वे सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गये। यह पुरस्कार भारत भूटान मैत्री संबंध को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान और उनके जन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है। मोदी जी ने कहा कि भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं मैं इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करता हूं। इस अवसर पर भूटान के पांचवे राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और शाही परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है।

इसी भावना के साथ सम्मान प्राप्त करने के बाद अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए, इस पुरस्कार को 140 करोड़ भारतीय को समर्पित करते हुए मोदी जी ने कहा कि भारत और भूटान के लोगों के बीच आत्मीयता उनके द्विपक्षीय संबंधों का अद्वितीय बनती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिमालयी राष्ट्र में भारत लोगों के दिलों में बसता है। मोदी जी ने कहा, महामहिम आप भूटान की समृद्ध संस्कृति को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके प्रयास भूटान के आंतरिक आनंद के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। भूटान ने दुनिया को सकल राष्ट्रीय खुशी की अवधारणा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भूटान का माइंडफूलनेस सिटी भी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संबंध अविभाज्य हैं हमारी मित्रता अविभाज्य है, हमारा आपसी सहयोग अविभाज्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विश्वास अटूट और यह दिन हमारे लिए बहुत खास है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमेशा इस बात से आश्चर्यचकित रहा है कि 140 करोड़ की आबादी वाले विशाल दक्षिण एशियाई देश भारत की तुलना में इतनी कम आबादी वाला भूटान सबसे करीबी साझेदार और सबसे अच्छा मित्र कैसे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हिमालयी राष्ट्र की यात्रा दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और समझ का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमें समय-समय पर अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत उनकी शासन प्रणाली में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। केवल एक चीज जो भारत को सावधान रहने की जरूरत है और भूटान को भी जो कि चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भूटानी शाही परिवार भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत सहज रहा है।

विशाल हिमालय और भारत के बीच बसे पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में अपनी सीमा साझा करते हुए भूटान और भारत एक अनूठी और स्थाई साझेदारी सांझा करते हैं जो आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित है। मोदी की थिंपू यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन और भूटान अपने सीमा विवाद का शीघ्र समाधान चाहते हैं,

जिसका भारत के सुरक्षा हितों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत, भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद पर चल रही बातचीत पर कड़ी नजर रख रहा है क्योंकि इससे नई दिल्ली के सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है खासतौर पर डोकलाम त्रि- जंक्शन में। इससे पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री तोबगे को उनके असाधारण सार्वजनिक स्वागत के लिए धन्यवाद दिया जिसमें पारो से थिम्पू तक की यात्रा के दौरान लोगों ने उनका अभिवादन किया, मोदी जी अपने इस भव्य व असाधारण स्वागत के लिए भूटान का आभार व्यक्त किया।

निष्कर्ष

नि:संदेह पिछले दो दशक से भारत के पड़ोस में चुनौतियों का विस्तार हुआ और वह अधिक जटिल तथा संभावित रूप से खतरनाक हो गई है। इन चुनौतियों में सबसे बड़ा कारण चीन का विस्तारवादी नीति को माना जाता है। चीन पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र व हिंद महासागर जैसे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने में लगा हुआ है। चीन यह चाहता है कि भारत अपने पड़ोसियों में उलझा रहे और विकास न कर पाए। पिछले कुछ दशकों से चीन पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपने विस्तारवादी मंशा को पूरा करने के दृष्टि से उथल पुथल मचा कर रखा है। दक्षिण एशिया के ऐसे अशांत माहौल में भी भूटान ने खुद को शांति, समृद्धि और विकास के द्वीप के रूप में खुद को स्थापित किया है। भूटान ने भारत के सद्भावना संकेतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इसके विकास में भागीदारी बनने की इच्छा जताई है। यह अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह उसने भारत के खिलाफ चीन का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है इसलिए यह भारत का दायित्व है कि वह अपने छोटे पड़ोसी के राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करें और उसके विकास में पूरी सहायता दें।

संदर्भ सूची

1.Dr.Juhi Shrivastava : INDIA -BHUTAN RELATIONS; Analysis Of Changing Dynamics
(From 2007-2017)

2.Shailendra kumar sinha, Anju kumari : INDO - BHUTAN RELATIONS

3.Rajesh S. Kharat : BHUTAN CONTEMPORARY ISSUES & PERSPECTIVE

4.Neil Fraser : GEOGRAPHY OF A HIMALAYAN KINGDOM BHUTAN

5. डॉ रमेश पोखरियाल निशंक : खुशियों का देश भूटान

6. द इंडियन एक्सप्रेस - भारत भूटान के विकास के प्रयासों में उसके साथ खड़ा रहेगा: प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष नेतृत्व को दिया अश्वासन (22 मार्च 2024)

7.द हिंदू- भारत के पुरुष प्रथम नीति के प्रतीक संबंध (20/3/2024)

8.डॉ विकास कुमार :भूटान का सामरिक महत्व एवं भारतीय सुरक्षा

9.रतन पाल: इंडो भूटान रिलेशंस

10. लक्ष्मण सिंह राठौड़ : दा चेंजिंग भूटान